छावनियों के लिए समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम / संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं

4596. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम/संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजनाएं लागू नहीं होती हैं;

(ख)यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग)सरकार द्वारा छावनी क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ)गत तीन-तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष छावनियों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई हैं?

रक्षा मंत्रालय (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही कार्यान्वित किया जा रहा हैं और इस समय यह छावनी क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा हैं। योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिशनिर्देशों के अनंसार क्षेत्रों का विचार किए बिना स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को संबंधित संसद सदस्य के विवेकाधिकार पर अपने क्षेत्र के अंदर उपयोग करने के लिए रखा जाता हैं;

(ग)पिछले तीन वित्त वर्षो के दौरान छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित योजनाओं का ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(घ)पिछले तीन वर्षो के दौरान 62 छाविनियों में विकास कार्ये पर हुए व्यय का ब्योरा इस प्रकार हैं:-

वर्ष	विशेष सहायता अनुदान सहित विकास कार्ये पर हुआ कुल व्यय
1994-95	7,29,08,407.000 रूपये
1995-96	10,14,77,491.000 रूपये
1996-97	18,74,09,995.000 रूपये

विवरण

योजनाओं/कार्यों का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
		लाख रूपये में	
जलापूर्ति	2.64	8.50	118.93
शुष्क सौचालयों को जलवाहित बनाना	-	132.27	84.826
सड़कें	-	16.47	-
भवन	-	-	-
विविध विकास	-	7.21	4.14
जोड़	2.64	164.45	207.896

Appointment of CSD Employees by Local Authorities

4597. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the employees of the CSD Canteen, AF Station, New Delhi, appointed by local authorities were sponsored by employment exchange;

(b) whether Government would order enquuy into the appointment, suspension, dismissal of employees of the said canteen over the last five years to bring to light nepotism, misuse of authority and high-handedness of certain officials; and